

>

Title : Need to construct roads under Public-Private Partnership Scheme in Chhatisgarh.

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): देश में सड़क परिवहन की सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से निजी वित्त को आकर्षित करते हुए पीपीपी योजना के अंतर्गत सड़कें बनाने की घोषणा जोर-शोर से की गई थी। लगभग चार साल बीतने के बावजूद छत्तीसगढ़ के (1) रायपुर-बिलासपुर, (2) बिलासपुर-उड़ीसा बार्डर, (3) सारंगढ़ से सराईपाली, (4) सिमगा से एमपी बार्डर और (5) आरंग बार्डर की सड़कों पर काम शुरू भी नहीं हो सका है। यह योजना लालफीताशाही की शिकार होकर रह गई है।

उपर्युक्त कारणों से छत्तीसगढ़ का प्रादेशिक सड़क घनत्व प्रति वर्ग सेंकड़ा कि.मी. पर राष्ट्रीय औसत 76.80 कि.मी. की तुलना में मात्र 26.18 कि.मी. ही रह गया है। अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के कार्य को शीघ्र शुरू किया जाये।